

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1917]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2015/भाद्र 17, 1937

No. 1917]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2015/BHADRA 17, 1937

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2015

का.अ.2452(अ).—केंद्रीय सरकार, बचक अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 102 की उपधारा (2) में (5) द्वारा प्रस्तावित मसिखों का प्रकोष करते हुए केंद्रीय बचक परिषद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् आंध्र प्रदेश राज्य बचक बोर्ड के विघटन के लिए और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए पृथक बचक बोर्डों के पुनर्गठन के लिए स्वीम का अनुमोदन करती है और इस प्रकार अनुमोदित स्वीम को प्रकाशी करने हेतु निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और धारण - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए राज्य बचक बोर्डों के विघटन और पुनर्गठन के लिए स्वीम का अनुमोदन आदेश, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं - इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से बचक अधिनियम, 1995 (1995 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) "निवृत्त दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जब वह आदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ग) "विद्यमान बोर्ड" से आंध्र प्रदेश राज्य बचक बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

3. विद्यमान बोर्ड का विघटन - निवृत्त दिन को और से, आंध्र प्रदेश राज्य बचक बोर्ड विघटित हो जाएगा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों अधिनियम की धारा 13 और 14 में अंतर्निहित उपबंधों के अनुसार उनके अपने-अपने राज्य बचक बोर्डों की स्थापना करेगी तथा इस प्रकार गठित बोर्डों की अधिकारिता आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में जाने वाले अपने-अपने क्षेत्रों पर होगी।

4. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बचक के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध - जहां अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया बचक, निवृत्त दिन से पूर्व विद्यमान बोर्ड के अधीनगामीन है, और ऐसे बचक से संबद्ध बचक संपत्ति -

- (i) पूर्वतया एक राज्य के भीतर स्थित है, ऐसा बक्क नियत दिन को उस राज्य की उत्तराधिकारी राज्य बक्क बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएगी;
- (ii) भागत: एक राज्य में और भागत: अन्य राज्य में स्थित है, ऐसी बक्क संपत्ति नियत दिन को बिना किसी और जांच, प्रभाव या फीस के, उन प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में स्थित संपत्ति के विस्तार तक रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएगी।

5. विद्यमान बोर्ड के अधिकारों और बाधितों का अंतरण - (1) विद्यमान बोर्ड के सभी अधिकार और बाधित (जिसके अंतर्गत इसके द्वारा की गई किसी संबिधा के अधीन अधिकार और बाधित है) उत्तराधिकारी राज्य बक्क बोर्डों को अंतरित किए जाएंगे।

(2) उत्तराधिकारी राज्य बक्क बोर्ड प्रसुविधाएं प्राप्त करेंगे और विद्यमान बोर्ड का विलीय बाधित भी बहन करेंगे।

(3) आस्तियों और बाधितों का प्रभावण, ऐसे विलीय समायोजन के मध्यमस्थ होना जो उत्तराधिकारी राज्य बक्क बोर्डों के मध्य आस्तियों और बाधितों के न्यायोचित, साम्यापूर्ण और सुकृतियुक्त प्रभावण हेतु आवश्यक होगा।

6. विद्यमान बोर्ड को आस्तियों का अंतरण - (1) चूंकि विद्यमान बोर्ड की स्थायी आस्तियां आंध्रप्रदेश और तेलगाना दोनों राज्यों के क्षेत्रों में विस्तारित हैं, सभी आस्तियों, जिनके अंतर्गत संपत्तियां, भूमि और भवन, वृक्ष और बाग तथा अन्य विन्यास, उनसे संबंधित अधिलेख और विजिटल अधिलेख हैं, के संबंध में "जैसी है, जहां है" सिद्धांत अपनाया जाएगा;

परंतु किसी बक्क से संबद्ध या बक्क संस्था से संबंधित कोई अन्य संपत्ति और जो, यथास्थिति, आंध्रप्रदेश या तेलगाना राज्य से बाहर स्थित है और विद्यमान बोर्ड के अधीक्षण के अधीन है, संबंधित उत्तराधिकारी राज्य बक्क बोर्डों के अधीक्षण के अधीन समझी जाएगी।

(2) सभी अन्य भंडार, वस्तु और अन्य मार्ग जिसके अंतर्गत विद्यमान बोर्ड से संबंधित इलेक्ट्रानिक माल यदि वह हृदराबाद से बाहर अवस्थित है, उस उत्तराधिकारी राज्य बक्क बोर्ड की संपत्ति बनेगा जिसके राज्य क्षेत्र में ऐसे भंडार, वस्तुएं और अन्य मार्ग अवस्थित हैं और यदि ऐसे भंडार, वस्तुएं और अन्य मार्ग जिसके अंतर्गत हृदराबाद में अवस्थित इलेक्ट्रानिक माल है, उनका वितरण आंध्र प्रदेश और तेलगाना राज्य बक्क बोर्डों के मध्य 45:55 के अनुपात में किया जाएगा;

परंतु केंद्रीकृत संगणना सुविधा जो विद्यमान बोर्ड की अधीक्षण के अधीन है, तेलगाना के राज्य बक्क बोर्ड को जाएगी और आंध्र प्रदेश राज्य बक्क बोर्ड के लिए केंद्रीय बक्क परिषद से विलीय सहयता से नई केंद्रीकृत संगणना सुविधा का पूरक किया जाएगा।

(3) पूर्व आंध्र प्रदेश सरकार से बक्क संस्थाओं से भूमि के अधीन के मध्य प्राप्त किए जा रहे विद्यमान बोर्डों के पास लगभग 40 करोड़ रुपये की स्थायी निधि उस पर ब्याज सहित ऐसे उत्तराधिकारी राज्य बक्क बोर्डों को वापस किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता के भीतर वे बक्क संस्थाएं स्थित हैं।

(4) हृदराबाद में राज्य हज हाउस भवन के समीप स्थलों में विद्यमान बोर्ड द्वारा 23 करोड़ रुपये का निमा गया विनिधान उस पर ब्याज सहित आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित बक्क संस्थाओं से प्राप्त ऐसे धन की सीमा तक आंध्र प्रदेश राज्य बक्क बोर्डों को दिया जाएगा तथा उसका उपयोग भूमि के ऋण और हज हाउस के समीप स्थलों पर बाणिज्यिक भवनों के विकास के लिए किया जाएगा।

(5) आंध्र प्रदेश राज्य में तेलगाना में स्थित हज हाउस में बक्क संस्थाओं से विनिधान किया गया धन उस पर ब्याज सहित आंध्र प्रदेश राज्य बक्क बोर्डों को केवल आंध्र प्रदेश हज समिति, उर्दू अकादमी और अल्पसंख्यक विस्त निगम द्वारा दखलकृत हज हाउस के परिसरों को खाली करने के पश्चात् वापस किया जाएगा।

(6) हज हाउस में स्थित प्राइवेट बाणिज्यिक संस्थाओं से संगृहीत भाटक आंध्र प्रदेश राज्य बक्क बोर्ड और तेलगाना राज्य बक्क बोर्ड के मध्य 45:55 के अनुपात में अपने-अपने राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या पर ऐसे समय तक साझा किया जाएगा जब तक आंध्रप्रदेश और तेलगाना राज्य सरकारों की राजधानी हृदराबाद संयुक्त रूप से बनी रहती है;

परंतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की राजधानी के नए स्थान पर अंतरण पर तेलगाना राज्य बक्क बोर्ड आंध्र प्रदेश राज्य बक्क बोर्ड को हज हाउस में विनिधान किए गए धन की पूरी रकम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बक्क संस्थाओं से प्राप्त ऐसे धन की सीमा तक, उस पर ब्याज के बिना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की राजधानी के अंतरण के छह मास के भीतर अंतरित करेगी।

(7) नियत दिन को विद्यमान बोर्ड के खाते में चालू रोक अतिशेष आंध्र प्रदेश और तेलगाना के उत्तराधिकारी राज्य बोर्डों के मध्य उन राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर 45:55 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

(2) निवृत्त दिन से पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में विद्यमान बोर्ड द्वारा या की ओर से कही गई सभी बातें या की गई कार्रवाई अन्तर्गत राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा की गई बातें या की गई कार्रवाइयां समझी जाएंगी।

14. विवादों का निपटारा - विराहीय आस्तियों और दायित्वों की रकम से संबंधित कोई विवाद अन्तर्गत प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मन्त्रालय पारस्परिक कठोर के माध्यम से निपटाया जाएगा, ऐसा न होने की दशा में ऐसे मामलों में केंद्रीय सरकार का विनिरचन बाध्यकारी होगा।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसे किसी विवादों का विनिरचन करेगी जिसके संबंध में अन्तर्गत प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारें कोई कठोर करने में विफल रही हों और केंद्रीय सरकार का ऐसा विनिरचन बाध्यकारी होगा।

[फा. सं. 8-10/2014-वक्फ]

राफेल मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
ORDER

New Delhi, the 7th September, 2015

S.O.2452(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) to (5) of section 102 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government, after consulting the Central Waqf Council and the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana, hereby approves the scheme for dissolution of the Andhra Pradesh State Waqf Board and for reconstitution of separate Waqf Boards for the States of Andhra Pradesh and Telangana and makes the following order to give effect to the scheme so approved, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This order may be called the Approval of Scheme for Dissolution and Reconstitution of the State Waqf Boards for the States of Andhra Pradesh and Telangana Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In this order, unless the context otherwise required,—

(a) "Act" means the Waqf Act, 1995 (43 of 1995);

(b) "appointed day" means the date on which this order is published in the Official Gazette;

(c) "existing Board" means the Andhra Pradesh State Waqf Board;

(d) "section" means section of the Act.

3. Dissolution of existing Board.— On and from the appointed day, the Andhra Pradesh State Waqf Board shall stand dissolved and the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall establish their own State Waqf Boards in accordance with the provisions contained in section 13 and 14 of the Act and the Boards so constituted shall have jurisdiction over the areas falling in the respective States of Andhra Pradesh and Telangana.

4. Provisions for registration of waqf in the States of Andhra Pradesh and Telangana.— Where, a waqf registered or deemed to be registered under the Act is under the superintendence of the existing Board prior to the appointed day, and the waqf property attached to such waqf is situated—

(i) wholly within one State, such waqf shall, as on the appointed day, be deemed to have been registered with the successor State Waqf Board of that State;

(ii) partly in one State and partly in another State, such waqf property shall, as on the appointed day, be deemed to have been registered, without any further enquiry, charge or fee, in each of those States to the extent of the property situated in each State.

5. Transfer of rights and liabilities of existing Board.— (1) All the rights and liabilities of the existing Board (including the rights and liabilities under any contract made by it) shall be transferred to the successor State Waqf Boards.

(2) The successor State Waqf Board(s) shall receive the benefits and also bear the financial liabilities of the existing Board.

(3) The apportionment of assets and liabilities shall be subject to such financial adjustment as may be necessary to secure a just, equitable and reasonable apportionment of the assets and liabilities among the successor State Waqf Boards.

6. Transfer of assets of existing Board.— (1) As the fixed assets of the existing Board are spread over the areas of both Andhra Pradesh and Telangana, the principle of "as is where is" shall be adopted in respect of all assets including properties, land and buildings, trees and orchards and other endowments, records and digital records relating thereto:

Provided that any other property attached to a waqf or belonging to a waqf institution which are situated outside the State of Andhra Pradesh or, as the case may be, Telangana, and are under the superintendence of the existing Board, shall be transferred to the successor State Waqf Boards.

(2) All other stores, articles and other goods including electronic goods belonging to the existing board shall in so far as they are located outside Hyderabad, become the property of the successor State Waqf Boards in whose territory such stores, articles and other goods are located and if such stores, articles and other goods including electronic goods are located within Hyderabad, they shall be distributed between the State Waqf Boards of Andhra Pradesh and Telangana in the ratio of 45:55 :

Provided that the Centralised Computing Facility which is under the superintendence of the existing Board shall go to the State Waqf Board of Telangana and a new Centralised Computing Facility shall be created for the State Waqf Board of Andhra Pradesh with the financial assistance from the Central Waqf Council.

(3) The fixed deposits of around rupees forty crores with the existing Board, being received from the erstwhile Government of Andhra Pradesh on account of acquisition of land from Waqf Institutions, alongwith interest thereon, shall be returned to the successor State Waqf Board within whose jurisdiction those waqf institutions are situated.

(4) The investment of rupees twenty-three crores made by the existing Board in the sites adjacent to the State Haj House building at Hyderabad shall be given to the Andhra Pradesh State Waqf Board, with interest thereon, to the extent such money was received from the waqf institutions situated within the State of Andhra Pradesh and utilised for purchase of land and for development of commercial buildings on the sites near the Haj House.

(5) The money invested from waqf institutions in the State of Andhra Pradesh in Haj House situated in Telangana shall be returned to the Andhra Pradesh State Waqf Board, without any interest thereon, only after vacating of the premises of Haj House occupied by the Andhra Pradesh Haj Committee, Urdu Academy and Minorities Finance Corporation.

(6) Rents collected from private commercial institutions located in Haj House shall be shared in the ratio of 45:55 between the Andhra Pradesh State Waqf Board and the Telangana State Waqf Board based on the Muslim population in the respective States till such time as the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana continue to jointly have Hyderabad as their Capital:

Provided that on the transfer of State Capital to a new location by the Government of Andhra Pradesh, the Telangana State Waqf Board shall transfer to the Andhra Pradesh State Waqf Board, the total sum of money invested in the Haj House to the extent such money was received from the Waqf institutions located in the State of Andhra Pradesh, without interest thereon, within six months of the transfer of State Capital by the Andhra Pradesh Government.

(7) Running cash balance in the account of the existing Board as on the appointed day shall be divided between the successor State Boards of Andhra Pradesh and Telangana in the ratio of 45:55 on the basis of Muslim population in those States.

(8) The distribution of vehicles of the existing Board between the successor State Boards of Andhra Pradesh and Telangana may be determined on the basis of total aggregate value of vehicles and the vehicles shall be allocated on the basis of aggregate value in the ratio of 45:55 between the two State Boards.

7. Recovery of outstanding contributions and dues.— The right to recover contribution and other dues payable, but not so recovered, as on the appointed day, in respect of any waqf property under the superintendence of the existing Board shall,—

(i) if the whole of the waqf property is situated in one State, as on the appointed day, belong to the State Waqf Board having jurisdiction over the areas within which such property is situated;

(ii) in all other cases, belong to the State Waqf Board of the State, where the property, as on the appointed day, is deemed to have been registered.

8. Apportionment of staff of existing Board.— (1) Every employee of the existing Board, who is a native of Andhra Pradesh, shall, on and from the appointed day, be transferred to and become the employee of the Andhra Pradesh State Waqf Board and the services rendered by such employees for all purposes, be deemed to be service rendered by the employee of the Andhra Pradesh State Waqf Board.

2) All other employees of the existing Board shall, on and from the appointed day, be transferred to and become employees of the Telangana State Waqf Board and the services rendered by such employees under the existing Board shall, for all purposes, be deemed to be services rendered by the employees of the Telangana Waqf Board.

3) The determination of nativity of the employee in the existing Board shall be in accordance with the criteria followed bifurcation of all other employees of the two State Governments of Andhra Pradesh and Telangana.

4) Every employee shall be entitled to, and be subject to, the same conditions of service and the same rights and liabilities as respects disciplinary matters as he was entitled to, and was subject to, immediately before the appointed day.

5) The employees who have taken loans and advances from the existing Board shall continue to pay the installments and liquidation thereof, to the successor State Waqf Board to which they are allocated.

819 GI/15-2

9. Transfer of records.— (1) All records (including digital records) and other documents belonging to the existing Board and exclusively relating to the Andhra Pradesh State shall, with effect from the appointed day, be handed over to the Chief Executive Officer of the Andhra Pradesh Waqf Board or to a person duly appointed by the Government of Andhra Pradesh in this behalf under the Act.

(2) All other records and documents belonging to the existing Board shall, with effect from the appointed day, belong to the Telangana State Waqf Board.

10. Special provisions relating to certain proceedings pending before the existing Board.— All proceedings pending before the existing Board immediately before the appointed day as are certified by that Board, having regard to the situation of the waqf properties and other circumstances, —

(i) which ought to be disposed of by the Andhra Pradesh State Waqf Board, shall as soon as may be after such certification, be transferred to the Andhra Pradesh State Waqf Board;

(ii) which ought to be disposed of by the Telangana State Waqf Board shall, as soon as may be, after such certification, be transferred to the Telangana State Waqf Board.

11. Legal proceedings.— Where immediately before the appointed day, the existing Board is a party to any legal proceeding instituted in any court or Tribunal in the State of Andhra Pradesh or in the State of Telangana, the Andhra Pradesh State Waqf Board or the Telangana State Waqf Board, as the case may be, shall be deemed to be substituted after that day as a party to such proceeding or added as a party thereto, and the proceeding may continue accordingly.

12. Regulations made by the existing Board to continue in force.— All regulations made by the existing Board and in force immediately before the appointed day shall, until altered by the successor State Waqf Boards, continue to be in force in the States of Andhra Pradesh and Telangana.

13. Saving of certain actions taken by the existing board.— (1) All things done or actions taken by or on behalf of the existing Board in the State of Telangana under the Act, before the appointed day, shall be deemed to be things done or actions taken by the Telangana State Waqf Board.

(2) All things done or actions taken by or on behalf of the existing Board in the State of Andhra Pradesh under the Act, before the appointed day, shall be deemed to be things done or actions taken by the Andhra Pradesh State Waqf Board.

14. Resolution of disputes.— (1) Any dispute regarding the amount of financial assets and liabilities shall be settled through mutual agreement between the States of Andhra Pradesh and Telangana failing which the decision of the Central Government in such matters shall be binding.

(2) The Central Government shall decide any issue in respect of which the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana fail to reach an agreement and such decision of the Central Government shall be binding.

[F.No.8-10/2014-Waqf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.